



समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका संख्या: 2375 /2006

याचिकाकर्ता:

बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय "बीएफ-1", राजीव प्लाजा,
ओपीपी. यूटीआई बैंक, बिलासपुर (छ.ग.)
द्वारा निदेशक अशोक अग्रवाल,
पिता श्री लालमोहन दास अग्रवाल, आयु लगभग 42 वर्ष,
निवासी क्रांति नगर, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा ।

बनाम

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. नगर निगम, द्वारा आयुक्त बिलासपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर (छ.ग.) ।

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अमृतो दास

उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य की ओर से श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव, स्थायी अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 9 नवंबर, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था:



1) यह रिट याचिका बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत परमादेश रिट के लिए दायर की गई है, जिसमें उत्तरवादीगण, विशेषकर नगर निगम, बिलासपुर को 27/03/2003 के समझौते के खंड 3 को लागू करने और क्रियान्वित करने हेतु निर्देश देने की मांग की गई है, जैसा कि आरक्षण रोस्टर प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (स्थानांतरणीय अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 1994 के नियम 8 (संक्षेप में "नियम") में दुकानों के आवंटन के संबंध में पार्टी संख्या 2 द्वारा समझौते का पालन किया जाएगा, अर्थात् याचिकाकर्ता का यह कहना है कि ऐसा न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

2) इस रिट याचिका को दाखिल करने से संबंधित पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

अत्यधिक आधुनिक और पूर्णतः सुसज्जित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना के उद्देश्य से, बिलासपुर नगर निगम (संक्षेप में "निगम") ने प्रमोटर-बिल्डर योजना (संक्षेप में "पीबीएस") के तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं। निविदा सूचना के जवाब में, याचिकाकर्ता ने "राजीव प्लाजा" नामक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत की। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निविदा सूचना में आरक्षण के संबंध में कोई खंड या श्रेणी शामिल नहीं की गई थी, लेकिन, जैसा कि याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के पैरा 5.3 में अभिकथन किया है, निगम अधिकारियों ने कुछ आरक्षणों को स्वीकार करने की बात कही थी, जिसे याचिकाकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि, बिलासपुर के बढ़ते शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की तात्कालिकता को देखते हुए, आरक्षण के विवाद को बाद में विचार करने के लिए छोड़ दिया गया था।

इसके बाद 27-03-2003 को पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ। यह सत्य है कि समझौते के खंड 3 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन, यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि उसने विरोध करते हुए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे और वह आरक्षण के लिए सहमत नहीं था।

3) याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने वाणिज्यिक बैंकों से भारी मात्रा में धन उधार लेकर दुकानें निर्मित की हैं, और निगम के इस आग्रह पर कि नियमों के नियम 8 के तहत प्रदान किया गया आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह सभी दुकानों का आवंटन कर सके, क्योंकि दुकानों के आवंटन के लिए आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आवश्यक व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं थी। इन परिस्थितियों में, यह रिट याचिका उपरोक्त वर्णित राहत के लिए दायर की गई थी।

4) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव को, जो श्री अमृतो दास के साथ उपस्थित हुए, तथा उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित को और उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के विद्वान स्थाई अधिवक्ता श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव को सुना।

5) श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने, प्रारंभिक बिंदु पर ही, यह इंगित किया कि नियमों का नियम 8 अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य या छत्तीसगढ़ के नवगठित राज्य में कभी भी पीबीएस में लागू नहीं किया गया था; याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण या औचित्य के इस प्रतिकूल व्यवहार के लिए अकेले चुना गया था; जैसा कि परिशिष्ट पी/5 से देखा



जा सकता है, यहां तक कि रायपुर नगर निगम ने भी अपने पीबीएस में नियमों के नियम 8 को लागू नहीं किया था। श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने हमारा ध्यान रिट याचिका के उप-पैरा 5.3 से 5.6 में कथित बातों की ओर आकर्षित किया और बताया कि रिट याचिका के इन उप-पैराओं में वर्णित कोई भी बात निगम द्वारा विशेष रूप से अस्वीकृत नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, निगम द्वारा याचिकाकर्ता के साथ किया गया व्यवहार एक घृणित भेदभाव के समान है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। श्री मनिंद्र श्रीवास्तव आगे यह तर्क दे रहे हैं कि अन्यथा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निगम का यह आग्रह कि दुकानों को नियम 8 और 27/03/2003 के समझौते के खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जाना चाहिए, जो कि पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है, क्योंकि दुकानों को खरीदने के लिए आरक्षित श्रेणियों से कोई व्यक्ति/आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, और इसलिए, प्रमोटर-बिल्डर द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में दुकानें खाली पड़ी हैं और सामाजिक और सार्वजनिक हित के लिए अप्रयुक्त हैं।

6) श्रीमती चित्रा श्रीवास्तव, निगम के विद्वान स्थाई अधिवक्ता ने, इसके विपरीत, हमारा ध्यान 27/03/2003 के समझौते के खंड 3 और नियम 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता समझौते का एक पक्ष होने के कारण उससे बाध्य है, और इसलिए, उसे निगम के आग्रह पर कोई वैध आपत्ति नहीं हो सकती है कि याचिकाकर्ता-प्रमोटर को दुकानों के आवंटन के मामले में 27/03/2003 के समझौते के खंड 3, जिसे नियम 8 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण प्रदान करना चाहिए।

7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विचारणीय बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में राहत देने के लिए कोई मामला बनाया है। यह सुस्थापित है कि कोई भी राज्य कार्रवाई जहां वह संचालित होती है, संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखी जा सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निगम संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' के भीतर एक वैधानिक प्राधिकरण है, और इसलिए, उसकी कार्रवाई भी संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखी जा सकती है। चूंकि समानता के समान संरक्षण और अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों जैसे राज्य की कार्यवाही तर्कसंगत, निष्पक्ष और मंमानीपूर्ण ना हो यह केवल इस प्रकरण में ही लागू नहीं होंगे जब किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया गया हो बल्कि उनके अधिकारों के संबंध में या उन पर देनदारियां थोपने, या विशेषाधिकार प्रदान करने के प्रकरण में भी लागू होंगे।

8) उपरोक्त सुस्थापित न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के आधार पर, जब हम प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हैं, तो हमें याचिकाकर्ता के साथ समान परिस्थितियों वाले अन्य प्रमोटर-बिल्डरों से भिन्न व्यवहार किए जाने का कोई कारण या औचित्य नहीं मिलता है।

9) पैरा 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6 में याचिकाकर्ता ने कहा है:

"5.3. तब, जब याचिकाकर्ता ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए निगम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना के माध्यम से 'राजीव प्लाजा' के रूप में जाने जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि निविदा सूचना में दुकानों के आवंटन के संबंध में आरक्षण का कोई



प्रावधान शामिल नहीं था। चर्चाओं और वार्ताओं के दौरान, निगम अधिकारियों ने हालांकि, यह स्पष्ट किया था कि कुछ आरक्षण किए जाने हैं। इस स्तर पर, यह दोहराना उचित होगा कि न तो अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में और न ही नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमोटर-बिल्डर योजना के तहत दुकानों के आवंटन में आरक्षण कभी लागू किया गया था। याचिकाकर्ता, उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर, श्रेणीबद्ध रूप से यह दावा करता है कि पिछले 10 वर्षों से जब से प्रमोटर-बिल्डर योजना लागू हुई है, तब से प्रमोटर-बिल्डर योजना में आरक्षण कभी लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी, विभिन्न स्थानों पर, निगमों ने प्रमोटर-बिल्डर योजना के तहत अनुबंध प्रदान करते समय आवंटन में आरक्षण की कोई शर्त नहीं लगाई है। निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं:

1. रवि भवन, रायपुर
2. एडमिनिस्ट्रेटर बंगला, रायपुर
3. मिलेनियम प्लाजा, रायपुर
4. बस स्टैंड, रायपुर
5. शहीद स्मारक - रायपुर
6. भानुस्थान व्यवसायिक परिसर, रायपुर
7. सी.आई. होम्स, भोपाल

पूरे राज्य में ऐसे कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं कि पुनर्गठन से पहले या विभिन्न स्थानीय निकायों, निगमों, प्राधिकरणों के पुनर्गठन के बाद भी, सरकार ने प्रमोटर-बिल्डर योजना के तहत निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वाणिज्यिक भवनों में कोई आरक्षण नहीं किया था।

5.4 इसके अतिरिक्त, निगम पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 (जिसे आगे अधिनियम, 1956 के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों या छत्तीसगढ़ स्थानान्तरणीय अचल संपत्ति नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत आवंटन में कोई वैधानिक दायित्व नहीं है कि वह आरक्षण प्रदान करे। अधिनियम, 1956 की धारा 80, निगम के निपटान में या उसके प्रबंधन के तहत नगरपालिका संपत्ति या संपत्ति के निपटान को नियंत्रित करने वाले प्रावधान बनाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 81, 81-ए, 82 आदि में निहित अन्य प्रावधान भी निगम को संपत्ति के निपटान के मामले में कोई आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, जिसमें विलेखों का अनुदान भी शामिल है। वर्ष 1994 के नियमों में, जो अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में बने थे और छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू हैं, जिन्हें "स्थानान्तरणीय अचल संपत्ति नियम, 1994" (जिसे आगे 1994 के नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के रूप में भी जाना जाता है, का नियम 8 दुकानों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान बनाता है और यह स्पष्ट रूप से कहता



है कि निगम द्वारा दुकानों में आरक्षण किया जाना है। इस प्रकार, इसी कारण से अतीत में भी विभिन्न निगमों ने प्रमोटर-बिल्डर योजना के मामलों में आवंटन में आरक्षण संबंधी कोई शर्त नहीं लगाई थी।

5.5 याचिकाकर्ता, अपनी स्थिति और शर्तों को स्पष्ट करने के लिए, इसलिए, निगम के साथ 06/03/2003 को "विरोध के तहत" दर्ज किए गए समझौते में प्रवेश करने से पहले एक पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी। निगम के कार्यालय में 04/03/2003 को प्राप्त पत्र की एक प्रति संलग्न है।

जिसे यहाँ अनुलग्नक पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसकी एक प्रति कलेक्टर और महापौर, नगर निगम, बिलासपुर के कार्यालय में भी जमा की गई थी।

5.6 यह कि निगम ने स्थिति से अवगत कराया था और निविदा सूचना में कोई शर्त नहीं थी, याचिकाकर्ता ने यह भी जोर दिया कि ऐसी कोई शर्त लागू नहीं की जानी चाहिए। जबकि बातचीत चल रही थी और यद्यपि निगम अधिकारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि अन्य निगमों में और बिलासपुर नगर निगम में भी प्रमोटर-बिल्डर योजना में आरक्षण की ऐसी कोई शर्त कभी लागू नहीं की गई थी, उन्होंने याचिकाकर्ता से अनुरोध किया कि वह इस विवाद को पार्टियों के बीच बाद में तय करने के लिए छोड़ दे और एक ऐसी स्थिति के साथ आगे बढ़े जहां एक नया राज्य अस्तित्व में आया था और बिलासपुर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर बन गया था और बढ़ती आबादी, बढ़ते वाणिज्यिक, वित्तीय, औद्योगिक गतिविधियों और बिलासपुर में राज्य स्तरीय संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तुरंत एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करना आवश्यक हो गया था। याचिकाकर्ता कह सकता है कि याचिकाकर्ता की इस बात पर जोर देने के कारण कि ऐसी कोई आरक्षण शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए, उस समय न केवल निगम के अधिकारियों ने बल्कि राज्य सरकार के शहरी प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता से अनुरोध किया था कि, फिलहाल, इस विवाद को पार्टियों के बीच समझौते के निष्पादन को रोकने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, एक खुला खंड समझौते में डाला जा सकता है ताकि भविष्य के लिए इस विवाद को हल किया जा सके। एक उत्साही नागरिक के रूप में, बिलासपुर के एक स्थायी निवासी, याचिकाकर्ता और स्थान के निदेशक ने नए राज्य के उद्भव की स्थिति को देखते हुए और बिलासपुर को एक सुंदर शहर में विकसित करने का आग्रह किया, याचिकाकर्ता ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पार्टियों के बीच समझौते में खुला खंड डाला जाएगा ताकि इस विवाद को तय किया जा सके। बाद में। इस बीच, याचिकाकर्ता ने निर्माण





कार्य को समय पर पूरा करने और शहर के मध्य में एक सुंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का वचन दिया था ताकि उसे शहर के निवासियों को प्रस्तुत किया जा सके। सभी प्रकार के आश्वासन निगम अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए थे और यह भी कि राज्य के अधिकारी आरक्षण के संबंध में निश्चित रूप से इस मामले पर विचार नहीं करेंगे और यदि अन्य सभी मामलों में प्रमोटर-बिल्डर योजना के तहत आवंटन में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, तो समझौते में उचित और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यह याचिकाकर्ता द्वारा 27/03/2003 को किए गए खंड 29 के गंभीर प्रतिनिधित्व के कारण था कि याचिकाकर्ता ने अनुबंध को आगे बढ़ाने और "राजीव प्लाजा" नामक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अस्तित्व में लाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया। याचिकाकर्ता और निगम के बीच 27/03/2003 को हुए समझौते की एक प्रति यहाँ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न है।

10. यह ध्यान देना आवश्यक है कि बातचीत और चर्चाओं के दौरान जो कुछ भी हुआ, जैसा कि उपरोक्त पैरा में बताया गया है, उसे निगम द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि निगम के पास पीबीएस में शामिल की जाने वाली शर्तों को बदलने, संशोधित करने या बदलने की कोई शक्ति या विवेक नहीं है। समझौते का खंड 29 यह प्रावधान करता है कि यद्यपि बिल्डर-प्रमोटर समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है, यदि बिल्डर-प्रमोटर किसी शर्त में संशोधन या भिन्नता और छूट प्राप्त करता है, तो निगम भी उस भिन्नता, संशोधन और छूट से बाध्य है। खंड 29 को पैरा 5.3 से 5.6 में बताए गए बातों के साथ पढ़ने के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि समझौते का खंड 3 दुकानों के आवंटन के मामले में आरक्षण प्रदान करने की बात करता है, नियमों के नियम 8 के अनुसार, निगम द्वारा अनुबंध प्रदान करते समय याचिकाकर्ता को दिए गए अनुबंध में आरक्षण पर जोर नहीं दिया गया था, बल्कि इस विवाद को बाद के चरण में विचार करने के लिए रखा गया था। दूसरे शब्दों में, बिलासपुर के बढ़ते शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भवन परिसर के निर्माण की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर दिए बिना कि याचिकाकर्ता को समझौते के खंड 3 की आवश्यकता का पालन करना चाहिए, याचिकाकर्ता को भवन परिसर के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, निगम ने किसी भी महत्वपूर्ण या सारवान परिस्थिति की ओर इशारा नहीं किया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करे कि याचिकाकर्ता के साथ समान परिस्थितियों वाले अन्य प्रमोटर-बिल्डरों से भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। 'समानों के साथ समान व्यवहार' संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रवाहित होने वाला एक संवैधानिक सिद्धांत है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमें श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क में काफी बल मिलता है कि आरक्षण के लिए निगम का आक्षेपित आग्रह एक घृणित भेदभाव के समान होगा।

11. आरक्षण के लिए निगम का आग्रह मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता का यह दावा कि आरक्षित श्रेणियों से दुकानों के आवंटन के लिए आवेदकों की आवश्यक संख्या नहीं है, निगम द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है। और जैसा कि हो सकता है, बहस के दौरान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें बताया कि आरक्षित श्रेणियों से आवेदकों को आवंटित



की जा सकने वाली पर्याप्त संख्या में खाली दुकानें हैं, लेकिन, दुर्भाग्य से, आरक्षित श्रेणियों से आवेदकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध नहीं है। निगम के इस अनुचित आग्रह के कारण ऐसी अव्यवहारिक स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ बिलासपुर के बढ़ते शहर की जरूरतों को पूरा करने के एक प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ, भवन परिसर का निर्माण किया गया है, बड़ी संख्या में दुकानों को आवंटित करने की अनुमति है। खाली पड़ी हैं, और इन दुकानों को आवंटित करने की कोई उम्मीद नहीं है, जब तक कि निगम आरक्षण पर जोर देता है। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एक सामाजिक उपयोगिता है और इसका उद्देश्य समाज की जरूरतों को पूरा करना है, और प्रमोटर-बिल्डर द्वारा निर्मित दुकानों को वर्षों तक खाली रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस दृष्टिकोण से भी देखें, तो हमारा मत है कि निगम का यह आग्रह कि उन्हें नियमों के नियम 8 के अनुसार आरक्षण के मामले में दुकानों को सख्ती से आवंटित करना मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता-बिल्डर द्वारा उजागर की गई स्थिति की विवेचना किये बिना मनमाना और अनुचित है। हम यह नहीं मानते हैं कि सार्वजनिक न्याय निगम द्वारा विशेष रूप से आरक्षण पर जोर देकर पूरा किया जाना चाहिए है, क्योंकि आरक्षित श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदक नहीं हैं। इस मामले में, हमारी राय में, सार्वजनिक हित की सेवा करने के बजाय निगम का कठोर दृष्टिकोण सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा। हमें निगम द्वारा आरक्षण पर जोर देने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। यदि निगम वास्तव में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को दुकानें उपलब्ध कराने के बारे में गंभीर होता, तो उसने आरक्षित श्रेणियों से आवश्यक संख्या में व्यक्तियों का पता लगाने और आवंटन के लिए विचारार्थ उनके मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए होते। यह स्वीकार किया जाता है कि निगम ने ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया।

12. परिणामस्वरूप, और उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका का निराकरण करते हैं और उत्तरवादीगण को नियमों के नियम 8 के अनुसार दुकानों के आवंटन के मामले में आरक्षण पर बल न देने का निर्देश देते हैं।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दोनों पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-

वी.के. श्रीवास्तव

न्यायाधीश

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वे अपनी भाषा में इसे समझ सकें। इसे किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसी को वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक: पंकज सिंह ठाकुर